नवजनवादी क्रांति की जीत के लिए सशस्त्र संघर्ष के राह पर आगे बढ़ना ही होगा।

पिछले तीन साल की मोदी की शासन में ब्राह्मणीय हिंदू फासीवाद हमलों से किसी भी एक उत्पीड़ित वर्ग या उत्पीड़ित सामाजिक जन समुदाय नहीं बची है। किसी भी विपक्षी पार्टी या एनजीओ इन हमलों को रोकने की दम नहीं है। अगर इन हमलों का मुकाबला करना है, तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) और पीएलजीए में सभी उत्पीड़ित जनता, उत्पीड़ित सामाजिक जन समुदाय संगठित व सशस्त्र होकर प्रतिरोध करना ही होगा। इसलिए हमारी केन्द्रीय सैन्य आयोग (सी.एम.सी), भाकपा माओवादी का आह्वान है कि सभी उत्पीड़ित जनता, उत्पीड़ित सामाजिक जन समुदाय, धार्मिक अल्पसंख्यकों व उत्पीड़ित राष्ट्र भाकपा (माओवादी) और पीएलजीए में हजारों-लाखों संख्या में भर्ती हो जाए।

पिछले वर्ष में समूचे देश में ऑपरेशन ग्रीनहंट हमलों का परास्त करने के लक्ष्य से हमारी पीएलजीए द्वारा संचालित साहसिक टीसीओसी और प्रतिरोध कार्रवाइयों में हासिल सफलताओं के बारे में बड़े पैमाने पर प्रचार करें। इस पूरी दिसम्बर माह में भर्ती अभियान संचालित करें।

☆ प्रतिक्रांतिकारी नयी 'समाधान' हमले का परास्त करें! दुश्मन के बलों को सफाया करते हुए, उनके पास से हथियार छीन लें!

☆ दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करना गुलामी से बराबर है! रंगबिरंगे लालच दिखाकर अपने पक्ष में झुकाने की दुश्मन की एल.आई.सी. नीति का मुहतोड़ जवाब दे!

☆ पार्टी, पीएलजीए और संयुक्तमोर्चा को संगठित करें!

☆ पीएलजीए में बड़ी संख्या में युवक-युवतियों को भर्ती करें!

☆ सामंती व साम्राज्यवादी विरोधी वर्ग संघर्ष को तेज करें!

☆ ब्राह्मणीय हिंदू फासीवाद के खिलाफ मजबूत व जुझारू आंदोलन का निर्माण करें!

☆ मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद जिन्दबाद!

☆ पीएलजीए जिन्दबाद!

☆ भाकपा (माओवादी) जिन्दबाद!

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ

केन्द्रीय सैन्य आयोग

भाकपा (माओवादी)

14-10-2017

संदेश

देश भर में गुरिल्ला युद्ध-जनयुद्ध को तेज व विस्तारित करें!

भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के सफाया के लिए दुश्मन द्वारा जारी प्रतिक्रांतिकारी व नयी रणनीतिक हमला 'समाधान' (2017-2022) को हराएं!

पीएलजीए के 17वें वर्षगांठ के अवसर पर 2 से 8 दिसम्बर तक क्रांतिकारी जोश-खरोश व स्फूर्ति के साथ मनाने
सभी पार्टी कमेटियों व सदस्यों, पीएलजीए के लाल कमांडरों व योद्धाओं, जन मिलिशिया बलों, क्रांतिकारी जन सरकारों व जन संगठनों के नेता व कार्यकर्ताओं तथा उत्पीड़ित जनता का केन्द्रीय सैन्य आयोग (सी.एम.सी.), भाकपा (माओवादी) आह्वान!

(जनता के लिए)

केन्द्रीय सैन्य आयोग

भाकपा (माओवादी)

आर्थिक व सामाजिक समस्याओं पर बड़े पैमाने पर जनता को राजनीतिक आंदोलनों एकजुट करना होगा। उन आंदोलनों को जनयुद्ध के साथ जोड़ना होगा। क्रांतिकारी, जनवादी संगठन, शक्तियों, व्यक्तियों, व्यापक जनता को एकत्रित कर व्यापक पैमाने पर मजबूत जन आंदोलन निर्माण करना होगा।

7. बदलती सामजिक परिस्थितियों के अनुरूप जनयुद्ध के कार्यनीतियां विकसित करने के लक्ष्य से सभी राज्यों/स्पेशल एरिया/स्पेशल जोनों में सामाजिक शोध व वर्ग विश्लेषण का कार्य संचालित करें! उनके आधार पर सही कार्यनीतियां रेखांकित कर ठोस परिस्थितियों के साथ सृजनात्मक रूप से जोड़कर जनयुद्ध को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएं!

8. पार्टी व फौजी नेतृत्वकारी कतारों व कार्यकर्ताओं के सैद्धांतिक स्तर का उन्नतीकरण के कार्यक्रम लागू करें!

9. पीएलजीए को राजनीतिक, सैनिक व सांगठनिक तौर पर मजबूत करें!

समूचे देश में हमारे आंदोलन के सभी इलाकों में पीएलजीए में नयी भर्ती को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना होगा। जन आधार को बढ़ाने के लिए वर्ग संघर्ष को तेज करते हुए, उसमें आगे आने वाली सक्रिय जुझारू शक्तियों का पहचान कर उनपर ध्यान देकर भर्ती करना होगा। जहां हमारी आंदोलन कमजोर है, सीमित व्यक्तियों को और सापेक्षिक तौर पर मजबूत इलाकों दसियों या सैकड़ों संख्या में भर्ती करना होगा।

केन्द्रीय सैन्य आयोग का आह्वान :

15 अगस्त 1947 की सत्तांतरण के बाद 70 साल बीत चुकी थी। इन 70 वर्ष के समय काल में देश के सभी तरह के और सभी रंग के राजनीतिक पार्टियां केन्द्र या राज्यों में गद्दी पर बैठ कर सत्ता चलायी थी। लेकिन इन सारे पार्टियां और इस देश की संसदीय व्यवस्था जनता के रोजमर्रा व मौलिक समस्याओं में से किसी एक को निपटने में पूरी तरह विफल हुई थी। भविष्य में भी इन राजनीतिक पार्टियों व संसदीय व्यवस्था जनता की समस्याओं को निपट नहीं पाएंगे। अभी नरेंन्द्र मोदी द्वारा प्रवचित 'नवभारत निर्माण' भी जनता के समस्याओं को निपट नहीं सकती। वह शोषक वर्गों और सुदृढ़ करने के सिवाय गरीबी, जातिवाद और धर्मवाद को उन्मूलन नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी का एजेण्डे पर विश्वास रखने का मतलब है, देश की जनता और एक बार धोखे का शिकार हो जाना। इसलिए देश की जनता और एक बार धोखे में न फंसे – इसके लिए

चाहिए – इस तरह की समझदारी जनता के अंदर बढ़ानी होगी।

3. भारत के शोषक-शासक वर्गों के युद्धोन्माद और अंधराष्ट्रवाद को भण्डाफोड़ करें!

देश के अंदर गरीबी, निरक्षरता, बीमारी, भुखमरी, किसान की आत्महत्याएं आदि सामाजिक आर्थिक समस्याओं से लोगों की ध्यान हटाने के लिए भारत के शोषक-शासक वर्ग युद्धोन्माद और अंधराष्ट्रवाद का भड़का रहा है। इनकी शिकार होये बिना लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना होगा। इनसे शिकार होने पर क्रांतियां विफल हो सकती हैं।

4. तेजी बढ़ती फासीवाद के खिलाफ पार्टी के हाथों मजबूत औजार के रूप में पीएलजीए और संयुक्तमोर्चा को ढालें (remould करें)!

तेजी बढ़ती फासीवाद समाज के अंतरविरोधों को और तेज करती है। परिणामस्वरूप क्रांतिकारी परिस्थितियां क्रांतिकारी संकट की ओर आगे बढ़ सकती है। इस तरह की स्थिति में राजनीतिक रूप से जागरूक शक्तियां अनुकूल स्थिति में रहेंगे। वे लोगों को प्रेरित कर लाखों की तादात में जन उभारों का निर्माण करने की भूमिका निभा सकती हैं। शक्ति-संतुलन में बदलाव ला सकती हैं। लेकिन वे इस भूमिका को निभाने के लिए पार्टी के हाथों में मजबूत औजार के रूप में पीएलजीए और संयुक्तमोर्चा को ढालने की तरह प्रयास करना होगा। इसके लिए वे राजनीतिक रूप से होने वाली बदलावों को समझना होगा, उनके अनुरूप खुद को विकसित करना होगा। पहलकदमी और लचीलापन हासिल करना होगा।

5. ब्राह्मणीय हिंदू फासीवाद के खिलाफ क्रांतिकारी शक्तियों, जनवादियों, प्रगतिशील शक्तियों, संगठनों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, धर्मनिरपेक्षों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं को एकजुट कर व्यापक संयुक्तमोर्चा और मजबूत व जुझारू आंदोलन को निर्माण करें!

6. आंदोलन के सभी इलाकों में साम्राज्यवाद विरोध, सामंतवाद विरोध, राज्य विरोध वर्ग संघर्षों को तेज करें!

व्यापक ग्रामीण इलाकों में जमींदारों, सूदकोरों, शाहुकारों के लूट व शोषण के खिलाफ खेतिहर-गरीब व मध्यम किसानों को मजबूत वर्ग संघर्षों में गोलबंद करना होगा। साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण के खिलाफ विस्थापन आदि राजनीतिक,

देश भर में गुरिल्ला युद्ध-जनयुद्ध को तेज व विस्तारित करें!
भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के सफाया के लिए दुश्मन द्वारा जारी प्रतिक्रांतिकारी व नयी रणनीतिक हमला 'समाधान' (2017-2022) को हराएं!

प्रिय कामरेडो व जनता!

2 दिसम्बर, 2000 भारतीय क्रांतिकारी इतिहास में हमेशा के लिए याद रखने की दिन है। साम्राज्यवादी, दलाल नौकरशाही पूंजीवादी व सामंतवादी शोषण व उत्पीड़न से देश के उत्पीड़ित जनता की मुक्ति के लिए भा.क.पा. (माओवादी) के नेतृत्व में जनमुक्ति छापामार सेना (पी.एल.जी.ए.) का गठित दिन के रूप में, समूचे देश की जनता सदा के लिए याद रखने की दिन के रूप में वह रह गयी है। हमारी पार्टी के संस्थापक, शिक्षक व भारतीय क्रांति के निर्माता, अमर शहीद कामरेड चारू मजुमदार और कामरेड कन्हाई चटर्जी के दिशानिर्देशन में हमारे प्रिय नेता व अमर शहीद कामरेड्स श्याम, महेश व मुरली के प्रेरणा से, हजारों शहीदों द्वारा मिली स्फूर्ति से उस दिन देश की उत्पीड़ित जनता व विश उत्पीड़ित जनता के अधूरे सपनों को साकार करते हुए पीएलजीए की स्थापना हुई। अगली 2 दिसम्बर को हमारी वीर पीएलजीए के 17 वर्ष पूरे होने जा रहा है। इस अवसर पर सभी पार्टी कमेटियों व कमानों, पार्टी सदस्यों, पीएलजीए के साहसिक कमांडरों व योद्धाओं, जन मिलिशिया बलों, क्रांतिकारी जन सरकारों व जन संगठनों के नेता व कार्यकर्ताओं तथा उत्पीड़ित जनता का केन्द्रीय सैन्य आयोग (सी.एम.सी.), भाकपा (माओवादी) लाल अभिवादन पेश करती है। पिछले एक साल में देश भर में ऑपरेशन ग्रीन हंट के प्रतिक्रांतिकारी हमले का परास्त करने के लिए चौतरफे (राजनीतिक, सैनिक व सांगठनिक आदि के तौर पर) प्रतिरोध करने की प्रयास में शामिल सभी कामरेडो को सीएमसी क्रांतिकारी अभिवादन पेश करती है। बुरकापाल सहित विभिन्न साहसिक हमलों को सफलतापूर्वक अंजाम देने की क्रम में अपने जान न्योछावर करने वाले वीर छापामार योद्धाओं को, कई मुठभेड़ों, फर्जी मुठभेड़ों में, भीतरघात व दुश्मन के कोवर्ट ऑपरेशनों में, दुर्घटनाओं में, जेलों में, सर्पदंश, बीमारी आदि कारणों से जान गंवाने वाले सभी अमर शहीदों को विनम्रतापूर्वक क्रांतिकारी

श्रद्धांजली अर्पित करती है। उनकी कम्युनिस्ट मूल्यों, साहसिकता, निडरता, जनता के प्रति उनकी समर्पण से हम सब सीख व प्रेरणा लेते हुए, उनकी अधूरे सपनों व अरमानों को पूरा करने की कसम खाएंगे। सीएमसी का विश्वास है कि देश भर में संचालित छापामार युद्ध कार्रवाइयों में घायल हुए कई कामरेड सीघ्र ठीक होकर झुजारूपूर्ण जोश से फिर से युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ेंगे।

इस अवसर पर 2 से 8 दिसम्बर तक समूचे देश में संघर्षतरत सभी इलाकों में, गांवों व शहरों में पीएलजीए के 17वें वर्षगांठ को क्रांतिकारी जोश-स्फूर्ति के साथ मनाने पार्टी के सभी कतारों, पीएलजीए यूनिटों, क्रांतिकारी जन सरकारों व जन संगठनों व जनता का सीएमसी आह्वान करती है। दुश्मन द्वारा जारी प्रतिक्रांतिकारी व नयी रणनीतिक हमला 'समाधान' (2017-2022) को हराने के लक्ष्य से पीएलजीए को संगठित करने के लिए मदद करने की तरह देश भर में इस अवसर पर पूरी दिसम्बर माह भर भर्ती अभियान संचालित करने का आह्वान करती है।

भारती की नवजनवादी क्रांति को सफल बनाने और एकता कांग्रेस-9वीं कांग्रेस द्वारा निर्देशित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आत्मसात होते हुए और प्रयास करते हुए, ऑपरेशन ग्रीनहंट हमले को हराने के लिए लड़ते हुए इस वर्ष लगभग 140 कामरेड शहीद हुए। इसमें 30 महिला कामरेड शामिल थे।

इसमें हमारी पार्टी के दो केन्द्रीय कमेटी सदस्य के साथ-साथ डीके में 98, बीजे में 19, तेलंगाना में दो, एओबी में 7, ओड़िशा में दो, पश्चिम बंग में एक, एमएमसी में दो, पश्चिमी घटियों में एक कामरेड शामिल थे। इसमें तीन राज्य कमेटी स्तर के कामरेड, सात जेडसी/डीवीसी कामरेड, तीन सब-जोनल कमेटी के कामरेड, 22 एसी/पीपीसी कामरेड, 50 से ज्यादा पार्टी व पीएलजीए के सदस्य, लगभग 40 क्रांतिकारी जन सरकारों व संगठनों तथा मिलिशिया कार्यकर्ता और लगभग 15 क्रांतिकारी जनता शामिल थे।

इन शहीदों में भारतीय क्रांति के नेता व हमारी पार्टी के केन्द्रीय कमेटी के सदस्य कामरेड नारायण सान्याल (बिजय दा, पोलिट ब्यूरो सदस्य), कामरेड कुप्पु देवराज (रमेश, योगेश), राज्य कमेटी स्तर के कामरेड्स रघुनाथ महतो (बीजे सैक सदस्य), हिमाद्रि राय (पश्चिम बंग के एससी सदस्य), अजिता (कावेरी, पश्चिमी घाटी एसजेडसी सदस्या) शामिल थे।

पीएलजीए के 17वें वर्षगांठ के अवसर पर इस साल भर में अपने जान

योद्धाओं को गुमराह करने की धोखेबाजी कार्यनीति से, बड़े पैमाने पर मनोवैज्ञानिक युद्ध से जोड़ लागू की जाती है। जनता की दिलों अपने अनुकूल ढालने की (perception management) रूप में अमल की जाती है। 'नवभारत' निर्माण के लिए भारत के शोषक-शासक वर्गों द्वारा तय रणनीतिक योजना साथ जोड़ कर देखने के बाद ही इस हमले के बारे में सामग्रिक रूप से एक समझ बना सकेंगे। इसलिए 'नवभारत' निर्माण के अंदर षड़यंत्र और समाधान हमले की फासीवादी स्वभाव के बारे में पार्टी कतारों व पीएलजीए योद्धाओं राजनीतिक तौर पर एक समझ बनाकर क्रांतिकारी जनता को समझाना होगा।

भारत की क्रांतिकारी आंदोलन को उन्मूलन करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा तय नयी प्रतिक्रांतिकारी योजना तो आक्रामक है ही, लेकिन उसकी मजबूत व कमजोर - दोनों को और उसे मुकाबला करने के लिए हमारे मजबूत व कमजोर दोनों को सही तरीके से विश्लेषण करना होगा। इस समझ पर आधारित होकर इस प्रतिक्रांतिकारी हमले का मुकाबला करने की आक्रमण व आत्मरक्षात्मक कार्यनीतियां तय करनी होगी। इस समझ को हमारी पार्टी व पीएलजीए कतारों तक, स्थानीय सांगठनिक इकाइयों और क्रांतिकारी जनता तक ले जाना होगा और उन सभी को दुश्मन के हमले का मुकाबला करने के लिए राजनीतिक रूप से तैयार करना होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है।

2. 'नवभारत' निर्माण के नाम पर भारतीय शोषक-शासक वर्ग अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने की इस योजना के बारे में देश भर में राजनीतिक तौर पर भण्डाफोड़ करने की प्रचार आंदोलनों तेज करें!

शोषक-शासक वर्ग द्वारा अपनायी जा रही जनविरोधी, देश विरोधी साम्राज्वाद-परस्त नीतियों से देश के उत्पीड़ित जनता के अंदर दिन ब दिन बढ़ती जा रही सामाजिक आशांति, क्रांति का स्रोत न बने - इसके लिए 'गरीबी उन्मूलन' के नाम पर ग्रामीण व शहरी गरीबों के लिए सिर्फ कुछ घर बनाने से गरीबी हल नहीं होगी, ग्रामीण व शहरी गरीब जनता की जमीन समस्या, उत्पादक साधनों पर सत्ता और राजसत्ता से संबंधित समस्या है। जब तक वह समस्या हल नहीं होगी तक तक शोषक-शासक वर्गों द्वारा अमल की जाने वाली सुधारें जो भी हो, गरीबी हल नहीं कर सकती। पिछले 70 सालों से शोषक-शासक वर्ग हमारे देश की जनता को झूठी विकास कार्यक्रमों से धोखेबाजी कर रही हैं। अभी इस 'नवभारत' निर्माण योजना भी और धोखा है। इस धोखे का शिकार नहीं बनाना

रहे नीतियां जिस तरह उन देशों में शोषक वर्गों के दक्षिणपंथी और फासीवादी पार्टियों की वृद्धि के लिए अवसर दे रही हैं, उसी तरह सर्वहारा वर्ग और कम्युनिस्ट पार्टियों के उद्‌भव होने तथा छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों के रूप में विकसित होने, उनके द्वारा जुझारू संघर्ष संचालित करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर रही हैं।

हमारे देश में साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाही पूंजीपति और सामंती शोषण व उत्पीड़न की तीव्रता के कारण रोजगार खो जाने वाले किसान, जंगलों पर अपनी अधिकार खो जाने वाले आदिवासी, नौकरियां खो जाने वाले मजदूर, कर्मचारी, नौकरियां मिलने कोई भरोसा महसूस नहीं करने वाले छात्र, ब्राह्मणीय हिंदू फासीवादी हमलों से शिकार दलित, मुस्लिम, आदिवासी, उत्पीड़ित राष्ट्र - सभी पहले के मुकाबले अभी व्यापक व जुझारू रूप से गोलबंद हो रहे हैं। यह रूझान और बढ़ सकती है। और व्यापक व जुझारू रूप से बढ़ सकने वाली ये ही आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन की अग्रगति के लिए व दुश्मन की हमले का परास्त करने के लिए बहुत बड़ी स्रोत व आधार है। अंतरराष्ट्रीय व देशीय तौर पर वृद्धि हो रही इन अनुकूलताओं के आधार पर उचित कर्तव्य व कार्यनीति तय कर दुश्मन की हमले को परास्त करेंगे। भारतीय नवजनवादी क्रांति को आगे बढ़ाएंगे।

कर्तव्य :

फरवरी 2017 के हमारी पार्टी की केन्द्रीय कमेटी द्वारा जारी की गयी 'वर्तमान परिस्थिति-हमारे कर्तव्य' नामक सर्कुलर में आम तौर पर अगले दो वर्ष के समय काल में पूरा करने वाले कर्तव्यों और कार्यनीतियों के बारे में दिशानिर्देशन जारी किया था। उन्हें ध्यान में रखकर निम्नांकित कर्तव्यों की पूर्ति के लिए प्रयास करना होगा।

1. भारत की क्रांतिकारी आंदोलन को सफाया करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिक्रांतिकारी 'समाधान' हमले (2017-2022) को हराने पर हमारे ध्यान केन्द्रित करें!

केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा तय की गयी नयी प्रतिक्रांतिकारी 'समाधान' हमला एक चौतरफा हमला ही है। एल.आई.सी. रणनीति के दिशानिर्देशन में तय की गयी इस हमला राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक व सांस्कृतिक के सभी क्षेत्रों में परम फासीवादी तरीकों में, क्रांतिकारी जनता, पार्टी कतारों व पीएलजीए

न्योछावर करने वाले सभी अमर शहीदों को याद करते हुए, विनम्रतापूर्वक सिर झुकाकर उन्हें क्रांतिकारी जोहार अर्पित करेंगे। उनकी अरमानों का पूरा करने के लिए आखरी तक लड़ने की शपथ लेंगे।

मिशन-2017 को हराने के लिए देश भर में हमारे द्वारा संचालित राजनीतिक, सैनिक व सांगठनिक प्रयास व उसके परिणाम :

समूचे देश में क्रांतिकारी आंदोलन का उन्मूलन के लिए केन्द्र व राज्य सरकारें 2014 शुरूआत से ही ऑपरेशन ग्रीनहंट के तीसरी चरण के हमले प्रारम्भ किया है। लेकिन नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए (नेशनल डेमोक्रटिक एलयेन्स-राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) केन्द्र में सत्ता पर आने के बाद देश भर में इन हमले और फासीवादी रूप ले लिया है और तेज व व्यापक होकर जारी है। मिशन-2016 को हमारी पार्टी के नेतृत्व में पीएलजीए-जन मिलिशिया, क्रांतिकारी जन सरकारें व जन संगठन तथा क्रांतिकारी जनता चौतरफे प्रत्याक्रमण कार्यनीतियों के साथ मुकाबला कर हराया था। इसके बाद दुश्मन द्वारा मिशन-2017 की योजना बनाया गया। हमारी आंदोलन के शक्ति-क्षमताओं के आधार पर देश भर में राजनीतिक, सैनिक व सांगठनिक प्रयास को तेज करने द्वारा मिशन-2017 को एक हद तक रोकने में हम कामयाब हुई। इसमें महत्वपूर्ण है - शोषक-शासक वर्गों के प्रतिक्रांतिकारी युद्ध का प्रतिरोध करते हुए जारी जनयुद्ध व छापामार युद्ध। इसके साथ-साथ रोजमर्रा व मौलिक समस्याओं पर जन आंदोलन को संचालित करना, संयुक्त मार्चे के गतिविधियां बढ़ाना, विस्थान विरोधी आंदोलनों को तेज व व्यापक करना आदि दुश्मन के हमले का मुकाबला करने में बहुती-ही मददगार साबित हुई। पार्टी और सैनिक क्षेत्रों में सभी स्तरों में नेतृतवकारी शक्तियों को शिक्षित करने के लिए नेतृत्वकारी प्रशिक्षण (Leadership Training) कैंपों को संचालित करने, नए कार्यनीतियों को बनाने के लक्ष्य से सामाजिक शोध करने, कृषि क्रांतिकारी कार्यक्रमों व क्रांतिकारी सुधारों को लागू करने द्वारा बेहतरीन परिणाम हासिल किए हैं।

अब मिशन-2017 को हराने के लिए पार्टी के नेतृत्व में पीएलजीए और क्रांतिकारी जनता द्वारा संचालित जनयुद्ध व छापामार युद्ध कार्रवाइयों का ब्यूरा पर नजर डालेंगे।

इस वर्ष डीके में 72 पुलिस, अर्धसैनिक व कमांडो बलों को सफाया कर 96 पुलिस वालों घायल किए हैं। दुश्मन के पास से 21 एके-47 रायफलों के

सहित 35 आधुनिक हथियार, लगभग 3,500 कारतूस जब्त किए हैं। इसी समय में 40 पुलिस मुखबिरों, दो जन दुश्मनों और छः दुश्मन के दलालों का सफाया किया गया है। जनता को विस्थापित करने वाली विभिन्न दलाल कार्पोरेट वर्गों के परियोजनाओं को रोकने के लिए कई जगहों पर रोड, पुल, मोबाइल टॉवर, रेल लाइन, गाड़ियों व इमारती लकड़ी को जला दिया गया और ध्वस्त किया गया।

डीके में संचालित जवाबी प्रत्याक्रमण अभियानों (TCOC) और प्रतिरोध कार्रवाइयों के तहत चार बड़े कार्रवाइयां - कोत्ताचेरुवु, बुरकापाल, कारमपल्ली, तोंडामरका हुई हैं। इनके साथ-साथ कई छोटे व मझौले कार्रवाइयां हुई हैं। इन कार्रवाइयां, खासकर बुरकापाल एम्बुश समूचे देश के क्रांतिकारी शिविर को ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी क्रांतिकारी शिविर में नयी उमंग व विश्वास बढ़ाया। इसी तरह दुश्मन के बलों का मनोबल पर गम्भीर चोट पहुंचायी।

डीके में संचालित टीसीओसी और प्रतिरोध कार्रवाइयां मिशन-2017 का दबर्दस्त व मुहतोड़ जवाब दिया। इन कार्रवाइयों के साथ-साथ देश भर में संचालित की गयी छापामार युद्ध कार्रवाइयों के साथ-साथ इनकी सफलता का नींव रखने वाली जन आधार की व्यापकता और आज की देशीय व अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति को ध्यान में रखकर दुश्मन अपनी रणनीति मिशन-2017 में बदलाव लाना पड़ा और 'समाधान' के नाम पर अगले पांच वर्षों (2017-2022) में भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को उन्मूलन करने की नयी प्रतिक्रांतिकारी योजना और रणनीति व कार्यनीति को तय करना पड़ा।

डीके में संचालित टीसीओसी व प्रतिरोध कार्रवाइयां छामापार आधार क्षेत्रों (गुरिल्ला बेस) की रक्षा करने में मददगार साबित हुई। बुरकापाल जैसे बड़े कार्रवाइयां गुरिल्ला बेसों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वर्ष के टीसीओसी द्वारा व्यापक रूप से प्राथमिक स्तर के इंप्रूवाइज्ड आर्टिलरी निर्माण व इस्तेमाल बढ़ने के कारण नए अनुभव मिली हैं। स्नाइपर कार्रवाइयों का व्यापकता बढ़ी। क्रांतिकारी आंदोलन के आपूर्ति के सभी तरह के स्रोतों को रोकने द्वारा पीएलजीए के युद्ध कार्रवाइयों के व्यापकता व तीव्रता को कम करने की केन्द्र व राज्य सरकारों की योजना का जवाब में डीके में छापामार युद्ध कार्रवाइयां नया अनुभव को लेकर क्रांतिकारी शिविर में आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। पीएलजीए बलों को केन्द्रीकरण कर बुरकापाल की तरह संयुक्त ऑपरेशनों को संचालित करना, स्थानीय स्रोतों पर निर्भर होकर प्राथमिक स्तर के आर्टिलरी का निर्माण करना, स्नाइपरों की तैयार करना, इंप्रूवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइजों के जरिए

मध्यपूर्व (पश्चिम एशिया), दक्षिण चीन सागर के इलाका, कोरियाई प्रायद्वीप साम्राज्यवादी अमेरिका, रूस और चीन के संघर्षों के केन्द्र बनी हुई हैं। चीन, उत्तर कोरिया के खिलाफ अमेरिका ने पांच लाख से ज्यादा अपने और दक्षिण कोरिया के फौजी टुकड़ों को एशिया-प्रशांत इलाके में भेजी है। साम्राज्यवाद चीन अपनी शोषण के हितों के लिए पहले से ही अपनी तैयारियां कर रही है। साम्राज्यवाद रूस एक तरफ चीन के साथ रिस्ता बढ़ाते हुए, मध्यपूर्व में अपनी स्थिति को कायम रखने के लिए अमेरिका के साथ लोहा ले रही है।

इस वर्ष मई महीने में चीन की राजधानी बीजिंग में ओन बेल्ट-ओन रोड (ओबीओआर) योजना के बारे में चर्चा करने के लिए चीन ने बेल्ट एण्ड रोड फोरम (बीआरएफ) के दो दिन के बैठक का आयोजन की है। इस बैठक में 29 देश के अधिनेता और एक सौ से ज्यादा देशों से प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ओन बेल्ट-ओन रोड योजना से अमेरिका को लग रही है कि विश्व अर्थ व्यवस्था में अपनी प्रभुत्व के लिए बड़ी चुनौती रूप में तब्दील होगी।

कमजोर होती जा रही अमेरिकी साम्राज्यवाद की प्रभुत्व को कायम रखने के लिए उस देश का राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा लागू नीतियां विश्व शांति के लिए गम्भीर खतरे के रूप में तब्दील हो रही है। ट्रम्प सत्ता में आने के तुरंत बाद सिरिया और अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक टुकड़ियों की तादाद बढ़ाकर वहां हमले तेज किया है। मध्यपूर्व को अपनी स्थायी शिविर के तौर पर तब्दील कर वहां के तेल और बाजारों को लूटने के लिए, इरान के खिलाफ साउदी अरब को खड़ा करते हुए उन दोनों देशों के बीच तनातनी भुजाने के सिवाय बढ़ाने की कुटिल उपाय अपना रहा है। इस दशाब्दी में 35,000 करोड़ डालर लाग वाली हथियार साउदी अरब को बेचने की समझौते किया है। साउदी अरब और इरान के विवाद से सुन्नी-शिया मतभेदों को जोड़कर मध्यपूर्व के सभी देश दो स्थायी विरोधी पक्ष के रूप में आमने-सामने होने की परिस्थितियों को सुलगता रहा है। चीन के विरोध में जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया और भारत को खड़ा कर रहा है। इन सभी बदलाव विश्व शांति के लिए गम्भीर खतरा पैदा कर रही है।

इसके परिणामस्वरूप क्रांति के अनुकूल बढ़ती बदलावों का विश्व सर्वहारा वर्ग, क्रांतिकारियों, क्रांतिकारी पार्टियां सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसके तहत हमारे देश में साम्राज्यवाद और देशीय दलालों के खिलाफ जनयुद्ध को तेज करने की जरूरत है।

वर्तमान साम्राज्यवाद देशों द्वारा आर्थिक और राजनीतिक तौर पर अपनाए जा

उद्योग के कर्मचारियों सहित अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों व छात्र आंदोलन का राह पकड़ रहे हैं।

एक देश-एक कर के नाम पर 1 जुलाई से लागू की गयी जी.एस.टी. (वस्तु और सेवा कर) नीति से देश भर में लाखों छोटे उद्यम और छोटे व्यापारी दिवालिया होकर, देश में सिर्फ बहुराष्ट्रीय कंपनियों व उनकी दलालों की उत्पादन और व्यापार संस्थान का ही दबदबा कायम होने की स्थिति पैदा हुई है। इससे देश के छोटे उद्यमियों और छोटे व्यापारी भी अगले दिनों में आंदोलन में उतरने की परिस्थितियां पनप रही हैं।

देश में ब्राह्मणीय हिंदू फासीवाद के हमले दलितों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं, उत्पीड़ित राष्ट्रों और प्रगतिशील बुद्धिजीवियों दिन ब दिन बढ़ रही है। इसके विरोध इन सभी तबके विभिन्न तरीके अपना कर संघर्ष कर रही हैं। हाल ही में, ये हमले बेरोकटोक जारी है। कर्नाटक में प्रमुख प्रगतिशील संपादक और लेखिका गौरी लंकेश की हत्या की गयी। गुजरात में उना दलितों पर हमला और उनका प्रतिरोध के बाद उत्तरप्रदेश के सहारनपुर आदि जगहों पर दलितों पर बेरोकटोक हमले जारी है। कश्मीर राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन और गोरखालैंड की मांग को लेकर जारी जुझार आंदोलन पर सेना और अर्धसैनिक बलों का प्रयोग कर उनका दमन तेज की गयी। विश्वविद्यालयों के छात्रों पर हमले बढ़ रही हैं। महिलाओं पर, विशेषकर, विश्वविद्यालयों में छात्रों पर पितृसत्तात्मक पाबंदियां लगाकर मनुधर्म को थोपा जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में ब्राह्मणीय हिंदू फासीवाद के खिलाफ स्थानीय स्तर से लेकर केन्द्र तक जहां-तहां एकजुट होकर, जुझारू व एकताबद्ध आंदोलन करने की दिशा में परिस्थितियां परिपक्व हो रही हैं। हिंदू फासीवादियों के हमले भारतीय समाज में मौलिक अंतरविरोधों को और तेज करते हुए क्रांतिकारी परिस्थितियों को और अनुकूल बना रही हैं। ये सब ब्राह्मणीय हिंदू फासीवाद विरोधी संयुक्तमोर्चा को गठित करने के लिए बहुत ही अनुकूलताएं उपलब्ध करा रही हैं।

वर्ष 2008 में अमेरिका में शुरू होकर पूरे विश्व में विस्तारित आर्थिक संकट की निपटारा अभी तक नहीं हो पायी है। सभी साम्राज्यवाद देश इस संकट को सुलझाने के लिए की गयी सभी प्रयास विफल होती जा रही है। इससे साम्राज्यवाद देश इसकी निपटारा के लिए आर्थिक तौर पर 'संरक्षण नीतियां', राजनीतिक रूप से फासीवाद और सैनिक रूप से युद्ध करने की मार्ग अपना रही है। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी मौलिक अंतरविरोध तीखी होती जा रही हैं।

माइन युद्ध तंत्र को तेज व व्यापक करना आदि इसी समय काल में डीके के छापामार जोन से हासिल नए अनुभव हैं। ये अनुभव देश भर में विभिन्न छापामार जोनों में व लाल प्रतिरोध इलाकों में पीएलजीए बलों को विकसित करने में मददगार होगी।

एओबी में 2016-2017 में संचालित टीसीओसी व प्रतिरोध कार्रवाइयों में 15 पुलिस मारे गये और 21 घायल हुए। इसमें मुंगारुगुम्मि-सुंकि एम्बुश बड़ा कार्रवाई थी। इसमें ओएसएपी (ओड़िशा राज्य के सशस्त्र पुलिस) के 9 जवान को सफाया और चार को घायल किया गया।

तेलंगाना में 2016-2017 में संचालित छापामार युद्ध कार्रवाइयों में चार पुलिस मारे गये और तीन घायल हुए। लम्बे अंतराल के बाद तेलंगाना में छापामार कार्रवाइयों में पुलिस वालों को सफाया करने में कामयाब होना अच्छा बदलाव है।

मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ (एमएमसी) में 2016-2017 में संचालित छापामार युद्ध कार्रवाइयों में चार पुलिस को सफाया और तीन को घायल किया गया। ओड़िशा में एक पुलिस को सफाया कर सात पुलिस को घायल किया गया।

इस तरह मध्य रीजियन के डीके, एओबी, तेलंगाना, ओड़िशा और एमएमसी में पिछले डेढ़ वर्ष के समय काल में 96 पुलिस मारे गये और 134 घायल हुए।

पूर्वी रीजियन के बिहार-झारखण्ड, पूर्वी बिहार-पूर्वोत्तर झारखण्ड, पश्चिम बंग राज्यों में पिछले 10 महीनों में पीएलजीए द्वारा संचालित 40 से ज्यादा प्रतिरोध कार्रवाइयों में 12 पुलिस मारे गये और सात घायल हुए। एक जनविरोध ी राजनेता और 10 प्रतिक्रांतिकारी तत्वों को सफाया किया गया। करोड़ों रूपयों के सरकारी, शोषक वर्गों और दलाल नौकरशाह कार्पोरेट कंपनियों के संपत्ति को ध्वस्त किया गया।

विगत 10 महीनों में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, झारखण्ड, एओबी, ओड़िशा, तेलंगाना, एमएमसी, पश्चिम बंग, पश्चिमी घाटियों के विभिन्न छापामार जोनों और लाल प्रतिरोध इलाकों में 200 से ज्यादा छापामार हमलों का पीएलजीए ने अंजाम दिया। इन हमलों में लगभग 110 पुलिस मारे गये और लगभग 135 पुलिस घायल हुए। लगभग 75 जन दुश्मनों, जन विरोधी राजनेताओं, प्रतिक्रांतिकारी तत्वों, मुखबिरों और कोवर्टों को सफाया किया गया।

इसके साथ-साथ हमारे क्रांतिकारी इलाकों में हजारों जनता को गोलबंद कर सामंत विरोधी, साम्राज्यवाद विरोधी और विस्थापन विरोधी जन आंदोलन, राज्यहिंसा के खिलाफ प्रतिरोध आंदोलन जिसमें बड़े पैमाने पर महिलाएं शामिल थी, चलायी गयी।

इस तरह अभी तक क्रांतिकारी इलाकों में आर्जित अनुभवों पर निर्भर होकर, डीके, बीजे आदि छापामार जोनों, लाल प्रतिरोध इलाकों और नए विस्तारित इलाकों में इन अनुभवों को ठोस परिस्थितियों के मुताबिक लागू करने के जरिए, विभिन्न इलाकों में संचालित छापामार युद्ध को तेज व व्यापक करने करने के जरिए, देश भर में बड़े पैमाने पर जनता को गोलबंद कर सामंत विरोधी व साम्राज्यवाद विरोधी वर्ग संघर्षों को तेज करने के जरिए हम बिना संकोच से साफ-साफ एलान कर सकते हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी 2017-2022 नयी प्रतिक्रांतिकारी योजना को भी हम हरा सकेंगे।

विगत वर्ष 2016 से तुलना करें तो, इस साल (10 महीनों में) देश भर में छापामार कार्रवाइयां तीव्रता और व्यपकता में जरूर वृद्धि आई है। इसके बावजूद दुश्मन के भीषण हमलों में हमारी पार्टी, पीएलजीए और आरपीसी-जन संगठनों के आत्मगत शक्तियां भी नुकसान उठाना पड़ा। इसके साथ-साथ उल्लेखनीय संख्या में हमारे हथियार और कारतूस भी दुश्मन के हाथों में चली गयी। जैसे कामरेड लेनिन कहा, वाकई में क्रांति प्रतिक्रांति का सामना करना जितना सही है, उस प्रतिक्रांतिकारी तत्वों को हराने द्वारा ही जनयुद्ध-गुरिल्ला युद्ध आगे बढ़ना भी उतना ही सही है। दुश्मन के योजनाओं के मुताबिक बराबर जवाबी कार्यनीति बनाकर व्यवहार में उन्हें अमल करने के लिए हमारी सभी ताकतों को केन्द्रीकृत करना, बोल्शेविक अभियान की रोशनी में विभिन्न गैरसर्वहारा रूझानों के खिलाफ पार्टी के नेतृत्व में पीएलजीए को सुदृढ़ करने और बड़े पैमाने पर जनता को गोलबंद कर उन्हें हथियारबंद कर जनयुद्ध को तेज करने द्वारा ही वह सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकती है।

बुरकापाल एम्बुश के उपरान्त दुश्मन द्वारा बनायी गयी नयी प्रतिक्रांतिकारी योजना ही है 'समाधान' रणनीति :

बीते वर्ष में संचालित टीसीओसीयों और प्रतिरोध कार्रवाइयों के तहत देश भर में हमारी पीएलजीए द्वारा चलायी गयी छापामार युद्ध कार्रवाइयां दुश्मन के मिशन-2017 के खिलाफ जबर्दस्त प्रतिरोध खड़ा किया। विशेष कर, बुरकापाल

मोदी के तीन साल शासन काल में 36 हजार किसान आत्महत्या की थी। इसी बीच फसलों को उचित मूल्य के लिए किसान मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में जुझारू आंदोलन किए हैं। अगले दिनों में किसान आंदोलन और जुझारू रूप ले सकती हैं और संगठित होकर आगे बढ़ सकती है।

कालाधन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद पर युद्ध के नाम पर मोदी सरकार अचानक बड़े नोटों को रद की है। यह कालाधन पर तो अंकुश लगा नहीं पाई, इसके विपरीत कृषि क्षेत्र, छोटे उद्योग, असंगठित क्षेत्र और खुदरा व्यापार माला-माल हो गयी। बड़े नोटों की रद करने के साथ-साथ मोदी सरकार की साम्राज्यवादी-परस्त नीतियों के कारण औद्योगिक विकासी धिमी पड़ गयी है। इन सभी के कारण भारतीय अर्थ व्यवस्था की 'विकास दर' बहुत गिर गयी है। मुद्रास्पीति बढ़ रही है। इससे छोटे उद्यमियों व व्यापारियों के साथ-साथ समाज के सभी तबके आर्थिक रूप से तीव्र मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है।

देश में 18 करोड़ शिक्षित बेरोजगार हैं। हर साल एक करोड़ लोगों को नौकरी व रोजगार दिलाना का मोदी की चुनावी वादा इन तीन सालों में साफ-साफ साबित हो गयी है कि वह झूठ है। इन तीन सालों में मोदी सरकार सिर्फ ढ़ाई लाख नौकरियां ही दे पाई है। हर साल एक करोड़ 30 लाख लोग डिग्री पढ़ाई पूरा कर रोजगार बाजार में शामिल हो रहे हैं। इन्हें रोजगार दिला नहीं पाने वाली जनविरोधी सरकारों के रूप में केन्द्र व राज्य सरकारें भण्डाफोड़ हो रही हैं। इससे आगामी दिनों में इस बेरोजगार सेना जुझारू आंदोलनों में उतरने की सम्भावनाएं बढ़ रही हैं।

वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकियों को ही पहली प्राथमिकता की (अमेरिकियों को ही पहले नौकरियों में लेकर, बेहतरीन वेतन देने की) नीतियां लागू करते हुए एच 1 बी वीसा के मामले में बदलाव लाया है। इससे अमेरिका जाकर नौकरी करने चाहने वालों को रोजगार अवसर घट गयी हैं। ब्रिटैन, आस्ट्रेलिया, सिंगपुर आदि साम्राज्यवाद, पूंजीवाद देश भी प्रवाशियों पर कई निषेध लागू की हैं। इससे भारतीय आईटी उद्योग में 5-6 लाख नौकरियां चले जाने की परिस्थिति पैदा हो गयी है। दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय तौर पर आर्थिक संकट जारी है, इससे विदेशों में भारत वासियों को नौकरियों से न सिर्फ निकाला जा रहा है, बल्कि नए अवसर न की बराबर हो गयी है। वहीं रंगभेद से भारतवासियों पर अमेरिका सहित कई देशों में हमले बढ़ रही है। इससे आइटी

दलाल नौकरशाह पूंजीपति व बड़े सामंती वर्गों के खिलाफ वर्ग संघर्ष और सशस्त्र संघर्ष करने वाले माओवादियों को कुचलने द्वारा, कश्मीर, उत्तर-पूर्व राष्ट्रीय-मुक्ति आंदोलनों को कुचलने (उनकी अर्थ में आतंकवाद से मुक्त करने) द्वारा 'हिंदू राष्ट्र' की स्थापना करना - ये ही है 'नवभारत निर्माण' का असली लक्ष्य। इसलिए भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को पूरी तरह सफाया करना ही 'नवभारत' निर्माण के पीछे भारत के शोषक-शासक वर्गों का लक्ष्य है। इन दोनों को जोड़कर देखने के बाद ही पता चलेगा कि 'समाधान' हमले कितना फासीवाद तरीका अपनाएगी।

इस प्रतिक्रांतिकारी नयी योजना व रणनीति-कार्यनीति के मुताबिक उसकी प्रधान केन्द्रीकरण दण्डकारण्य और बिहार-झारखण्ड पर होने के बावजूद, समूचे देश में क्रांतिकारी आंदोलन को उन्मूलन करना ही उसकी लक्ष्य है। इसका मुकाबला कर हराने के लिए जनता को व्यापक तौर पर जागरूक करने व संगठित करने की प्रयास सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने के लिए पूरी क्रांतिकारी शिविर तैयार होना चाहिए।

देशीय और अंतरराष्ट्रीय तौर पर क्रांति के पक्ष में बढ़ती परिस्थिति को इस्तेमाल करन दुश्मन के हमले को परास्त करेंगे :

1991 से लेकर आज तक विगत 26 वर्षों में केंन्द्र व राज्य सरकारें भूमण्डलीकरण नीतियों, उसके तहत मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियों लागू करने के कारण मजदूर व किसान जनता के जीवन दूभर हो गयी है। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र बहुराष्ट्रीय कार्पोरेटों के हाथों में होते हुए मजदूरों के नाम के वास्ते रही अधिकार कुचला जा रहा है। इसके कारण संगठित व असंगठित क्षेत्र के लाखों मजदूरों की रोजगार चले जाने के कारण सड़कों में उतर कर संघर्ष का रास्ता अपना रहे हैं। मजदूर आंदोलनों पर, उनकी नेतृत्वकारियों पर भीषण दमन लागू किया जा रहा है। कई मजदूर नेता अवैध मामलों में जेलों में ठूंसा जा रहा है और आजीवन कारागार सजाएं भी काटने स्थिति पैदा हुई है। इसके बावजूद देश भर में जुझारू मजदूर आंदोलन जारी है। दूसरी तरफ कृषि क्षेत्र संकट में फंसी हुई है। फसलों पर उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण खर्ज के बोझ से किसान जीवन बिताने पर मजबूर है। विश्व बैंक के आदेशों को विगत ढ़ाई दशकों से केन्द्र व राज्य सरकारें लागू करने के कारण भारतीय कृषि क्षेत्र ध्वस्त हुई है। छोटे व मध्यम वर्ग के किसानों जीवन चिन्न-भिन्न हो गयी है। इसलिए विगत ढ़ाई दशकों ढ़ाई लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या की थी।

एम्बुश के उपरान्त भारत के शोषक-शासक वर्ग और केन्द्र व राज्य सरकारों में बहुत हड़कंप मच गयी। तुरंत 8 मई को दिल्ली में केन्द्रीय गृहमंत्री के अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजन की गयी और भारती की माओवादी आंदोलन को उन्मूलन करने के लिए नयी प्रतिक्रांतिकारी योजना-रणनीति व कार्यनीति बनायी गयी। इस प्रतिक्रांतिकारी योजना के मुताबिक अगले पांच वर्षों (2017-2022) में देश में माओवादी आंदोलन को उन्मूलन करने की लक्ष्य रखी गयी है। इस प्रतिक्रांतिकारी योजना के रणनीति-कार्यनीति के मुख्य पहलू निम्न प्रकार है :

1. माओवादी विरोधी अभियानों में हिस्सा लेने वाले पुलिस, अर्धसैनिक व कमांडों बल आत्मरक्षात्मक तरीकों को छोड़ कर पूरी तरह आक्रामक हमले करने, माओवादी आंदोलन के मजबूत इलाकों के अंदर घुस कर हमले करने का निर्णय लिया गया है। यानी हमारी गुरिल्ला बेसों और रणनीतिक इलाकों पर केन्द्रीकृत हमले हो सकती है।
2. भारतीय वायुसेना और विभिन्न अर्धसैनिक बलों के एयरबोर्न (युद्ध विमान व हेलिकाप्टरों से हमले करने वाली) बलों के हवाई हमले करने का निर्णय लिया गया है।

   हवाई हमले करने के लिए, माओवादी हमलों में घायल हुए पुलिस वालों ले जाने के लिए 24 घंटे एयर सपोर्ट उपलब्ध कराने की तंत्र बस्तर संभाग के विभिन्न इलाकों में स्थापित कर रहे हैं। अगले दिनों में हमारे आंदोलन के मजबूत इलाकों/रणनीतिक इलाकों में जरूरत के मुताबिक इस तरह की हमले करने के लिए एयर सपोर्ट उपलब्ध कराने की तंत्र स्थापित कर सकते हैं। इन सबों के आधार पर पीएलजीए के बलों पर रात में भी हमले तेज किया जा सकता है।
3. खुफिया तंत्र को और विस्तारित व मजबूत करने का निर्णय लिया है। ह्यूमन इंटेलिजेन्स (मानव आधारित खुफिया तंत्र) सहित विशेष कर टेकनिकल और इलेक्ट्रोनिक इंटेलिजेन्स को विस्तारित व मजबूत करने का निर्णय लिया है। यूएवी/ड्रोन, उपग्रह (साटिलाइट), थर्मल इमेजिंग, इनफ्रारेड टेकनोलोजी, सीसी टीवी कमेरा, रॉडारों को इस्तेमाल कर खुफिया सूचनाएं इकट्टा करने का निर्णय लिया है।

   हमारे लिए सिविल और फौजी आपूर्ति उपलब्ध कराने और अन्य काम करने वाले लोगों को ढूंढ़ निकाल कर उन्हें मुखबिर-कोवर्टों के रूप में

बदलने की प्रयास तेज कर सकते हैं। विभिन्न तरह के टेकनिकल और इलेक्ट्रोनिक इंटेलिजेन्स तंत्र के जरिए पीएलजीए गतिविधियों पर लगातार निगरानी तेज कर सकते हैं।

4. इन प्रतिक्रांतिकारी हमलों को सक्षम तरीके से संचालित करने के लिए अभी तक कोलकता में मौजूदा सीआरपीएफ रणनीतिक कमान केन्द्र को रायपुर में स्थानांतरित कर दिया गया है। अभी तक छत्तीसगढ़ में राज्य स्तर में मौजूद एकीकृत कमान के साथ-साथ जिला स्तर में ऑपरेशनल और टैक्टिकल एकीकृत कमानों को गठित करना का निर्णय लिया है। इसके मुताबिक जिला स्तर में अभियानों के लिए योजना बनाने हेतु विभिन्न जिलों के नागरिक (सिविल) अधिकारी, अर्धसैनिक व वायुसेना के अधिकारी - सभी को मिला कर एकीकृत ऑपरेशनल कमानों को गठित करने के साथ-साथ उन अभियानों का क्षेत्र में संचालित करने के लिए जाने वाली सभी तरह के केन्द्र व राज्य बलों उच्च अधिकारियों के साथ कार्यनीतिक एकीकृत कमानों का गठन कर सकते हैं।
5. केन्द्र व राज्य पुलिस बलों के बीच समन्यव में खामियों को सुधार कर बेहतर समन्वय हासिल करने का निर्णय लिया है। इसके मुताबिक कंबैट ऑपरेशनों, सड़क निर्माण कार्य के लिए सुरक्षा, आरओपी आदि का अभियानों में शामिल होने वाले बलों के मदद में जरूर एक तिहाई राज्य के बल हिस्सा लेने और उन स्थानीय बलों को आगे रखना का निर्णय लिया है।
6. साम्राज्यवाद और दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग के लूट के लिए जरूरी मौलिक सुविधाओं की स्थापना करने के लिए अपने द्वारा लागू की जाने वाली योजनाओं पर 'विकास' का मोहर लगाना और उन्हें विरोध करने और उनके सुरक्षा में लगे पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर हमला करने पर उन कार्रवाइयों का 'विकास विरोधी' नाम देकर हमारे ऊपर बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार अभियान संचालित करने का निर्णय लिया है।
7. काउण्टर इंसर्जेन्सी और काउण्टर टेरारिस्ट ऑपरेशनों में इज्रायल की मदद लेना का निर्णय लिया है। माओवादी बलों पर हमले करने भारतीय अर्धसैनिक बल व वायसेना को इज्रायल द्वारा प्रशिक्षण दिला रहा है। अत्याधुनिक, बयोटेक हथियारों व टेकनोलोजी की आयात कर रहे हैं।

8. दण्डकारण्य के सुकमा जिले को कोर एरिया के रूप में चयनित कर हमले करने के लिए विशेष योजना बनायी गयी है। इसके लिए दो कोबरा बटालियनों की तैनात करने का निर्णय लिया है।
9. माओवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उनकी आर्थिक स्रोत पर चोट पहुंचाने का निर्णय लिया है।

उक्त रणनीति-कार्यनीति लागू करने के लिए आठ मोर्चों पर काम करने का प्रस्ताव से आठ अक्षरों को निकाल कर 'समाधान' शब्द बनाया गया, उसी को अपनी वर्तमान रणनीति के रूप में केन्द्रीय गृहमंत्रालय द्वारा पेश किया गया : एस-स्मार्ट लीडरशिप (सक्रिय नेतृत्व), ए-एग्रेसिव स्ट्रॉटजी (आक्रामक रणनीति), एम-मोटिवेशन एण्ड ट्रेनिंग (प्रेरित करना और प्रशिक्षित करना), ए-एक्शनबुल इंटेलिजेन्स (कार्रवाई में इस्तेमाल की जाने वाली गुप्त समाचार), डी-डॉश बोर्ड बेस्ड इंडिकेटर्स (हाथ में उपलब्ध सूचक), एच-हार्नेसिंग टेकनोलोजी (टेकनोलोजी का इस्तेमाल करना), ए-एक्शन प्लान फार ईच थ्रेट (प्रत्येक चुनौती का सामना करने की उचित कार्य-योजना), एन-नो एक्सेस टु फाइनॉन्सिंग (आर्थिक स्रोतों पर रोक लगाना) - SAMADHAN - समाधान - यही रणनीति है।

15 अगस्त के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा क्विट इंडिया के 75वें वर्षगांठ तक यानी 2022 तक भारत देश को 'नयी भारत' के रूप में विकसित करने का एजेंडा एलान किया गया। मोदी का आह्वान के मुताबिक इसका घोषित लक्ष्य है - कचड़ा मुक्त स्वच्छ भारत, गरीबी का उन्मूलन कर विकसित भारत, भ्रष्टाचार-मुक्त, आतंकवाद से मुक्त, जातिवाद-धार्मिकवाद (fundamentalism) से मुक्त भारत को गठित करना। यह सिर्फ आम जनता को भ्रम में डालने के सिवाय और कुछ नहीं है। इस घोषित एजेंडा के पीछे छिपी हुई असली लक्ष्य यही है कि देश को साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीपति व बड़े सामंती वर्गों के हितों के लिए किसी तरह की अवरोध पैदा न हो - इस तरह की भारत का गठित करना और साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीपति व बड़े सामंती वर्गों की सत्ता का सुदृढ़ करना। एक तरफ अमेरिकी साम्राज्यवाद के प्रति दक्षिण एशियाई वफादार रूप में भारत को खड़ा कर चीन का मुकाबला करना; दूसरी तरफ देश में उच्च-जातियों की प्रभुत्व को सुदृढ़ करने के लिए उत्पीड़ित जातियों, विशेषकर, दलितों को कुचलने (उनकी अर्थ में जातिवाद से मुक्त करने) द्वारा, धार्मिक अल्पसंख्यकों को दबाने (उनकी अर्थ में धर्मिकवाद से मुक्त करने) द्वारा ब्राह्मणीय हिंदू फासीवाद को मजबूत करना; साम्राज्यवाद,